हिन्दुस्तान 08-01-2016

सात रिसर्च प्रयोगशालाएं होंगी हाईटेक, बची हुई पांच क्लासें बनाई जाएंगी स्मार्ट, 20 करोड़ का बजट देने का वायदा

अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनेगा शर्करा संस्थान

शर्करा संस्थान के हॉल में मंत्री रामविलास का उद्‌बोधन सुनते छात्र व कर्मचारी। रिबन काटकर हॉस्टल का उद्‌घाटन करते मंत्री पासवान के साथ सांसद देवेंद्र सिंह भोले। • हिन्दुस्तान

कानपुर | वरिष्ठ संवाददाता

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान का कद बढ़ने वाला है। तीन वर्ष में अंतरराष्ट्रीय मानक के मुताबिक संस्थान को तैयार किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने इसकी घोषणा गुरुवार को की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानक के लिए जरूरी संसाधनों को 20 करोड़ रुपए जल्द से जल्द दिलाने का वादा किया है। इसका प्रस्ताव बनाकर निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान भेजेंगे।

केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने गुरुवार को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने इंस्टीटयूट की ओर से तैयार किए गए प्रेजेंटेशन को दखा। एक वर्ष में किए गए कामों की स्थिति को समझा। इसके बाद लैब और स्मार्ट क्लास रूम का जायजा लिया।

निदेशक प्रो.नरेंद्र मोहन ने बताया कि मंत्री ने बचे हुए 5 क्लास रूम को भी स्मार्ट करने और सात प्रयोगशालाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक तैयार करने को कहा। इनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के उपकरण लगाने की बात हुई। उन्होंने 21 शिक्षक दिलाने का वादा किया। एफसीआई के महाप्रबंधक देवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के प्रयासों से 500 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

सुरक्षाकर्मियों से हुई हाथापाई : राष्ट्रीय अध्यक्ष राम विलास पासवान से मिलने को लोजपा के कार्यकर्ता शर्करा संस्थान पहुंच गए। लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने धकियाया तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई कार्यकर्ता तक भड़क गए। सुरक्षा कर्मियों व लोजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं हुई।

छात्र बढ़ें मेक इन इंडिया की ओर

छात्रों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि मेक इन इंडिया से छात्रों के लिए अवसर बढ़े हैं। शुरुआत से ही छात्रों को शत प्रतिशत रोजगार मिल रहा है। वह संस्थान की ओर से दी जा रही सुविधाओं का फायदा उठाएं। अगर दिक्कत हो तो बताएं। मौका मिले तो छात्र मेक इन इंडिया की ओर बढ़ें। इससे छात्र के साथ ही संस्थान को भी बढ़ावा मिलेगा। छात्रों में उद्यमशीलता विकसित करने की जरूरत है।

20 अगस्त को दीक्षांत समारोह

2007 में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान का दीक्षांत समारोह हुआ था। इस बार फिर 20 अगस्त को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान का दीक्षांत समारोह होगा। इसी दिन से संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की शुरुआत की जाएगी। इसमें वह एक बार फिर से आएंगे। तीन वर्ष के अंदर संस्थान को उन्नत करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाना है।

राम विलास व भोले सम्मानित

संस्थान ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक प्रो .नरेंद्र मोहन ने केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान और सांसद देवेंद्र सिंह भोले को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने संविदा कर्मचारियों का मामला उठाया तो उन्होंने जल्द से जल्द कर्मचारियों की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने संस्थान के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए संकल्प दिलाया।

यूपी की मिलों में उत्पादन कम क्यों?

विभागीय बैठक मे केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र की चीनी मिलों से उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का उत्पादन कम होने पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने निदेशक प्रो.नरेंद्र मोहन से सुझाव भी मांगे। उन्होंने इस परिपेक्ष्य में बताया कि यूपी में 15 फीसदी अनइम्प्रूव्ड वैरायटी लगी हुई है। इसमे सुधार होना चाहिए। गन्ना खरीद सिस्टम में सुधार किया जाए। कटाई के 24 घंटे के अंदर गन्ने की पेराई हो जाए। परिपक्वता से पेराई कराई जाए।

छात्रों को समर्पित होगा नया हॉस्टल

केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान और सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने रिबन काटकर पूर्व निदेशक एससी गुप्ता के नाम पर हॉस्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने निदेशक के साथ अंदर जाकर पूरे हॉस्टल को देखा।36 कमरे के नए हॉस्टल को जुलाई में छात्रों को समर्पित किया जाएगा। इसमें 72 छात्रों के रहने की व्यवस्था की गई है। हॉस्टल में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी।

उपभोक्ताओं को धोखा देने पर अफसर नपेंगे : पासवान

कानपुर | वरिष्ठ संवाददाता

उपभोक्ता को धोखा देने में अब कंपनियों के साथ ही सरकारी विभाग और उनके अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके लिए एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथारिटी नियुक्ति की जाएगी। वह उपभोक्ता के साथ धोखा होने पर मामले को खुद संज्ञान में लेकर सरकारी व प्राइवेट कंपनी और विभागों पर कार्रवाई कर सकेंगे। यह जानकारी केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने गुरुवार को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में दी है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में संशोधन करके लोकसभा से पास हो गया है। अब एक्ट स्टेंडिंग कमेटी के पास है। संशोधन से उपभोक्ताओं को काफी फायदा मिलेगा। इसमें उपभोक्ता कोर्ट को मजबूत किया गया है। न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। 21 दिन के अंदर अगर शिकायत दर्ज नहीं की तो खुद ब खुद दर्ज मानी जाएगी। मामले की पैरवी करने के लिए वकील की जरूरत नहीं है। खुद पैरवी कर सकते हैं। आपस में समझौता हो सकता है। वहीं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) एक्ट 1986 है। नया बिल लाए हैं। इसमें अलग-अलग वस्तुओं का नाम देश में तो अलग होगा लेकिन देश के बाहर नाम एक हो जाएगा। जिससे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ सके। इसमें मुख्य रूप से संयुक्त भारत सरकार प्रशांत त्रिवेद्वी, एफसीआई के महाप्रबंधक देवेंद्र सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।

मिलेंगे अधिकार

- कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 संशोधन में उपभोक्ता को राहत, वकील की जरूरत नहीं उपभोक्ता खुद कर सकते हैं पैरवी
- कोर्टों में तैनात होगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अर्थोरिटी, गड़बड़ी व उल्लंघन पर खुद संज्ञान लेकर कर सकेंगे कार्रवाई

देश में पौने चार करोड़ फर्जी राशनकार्ड हटे

कानपुर। वर्तमान में देश के अंदर करीब पौने चार करोड़ फर्जी राशन कार्ड चल रहे थे। ऐसे फर्जी राशन कार्डो को हटा दिया गया है। फूड सिक्योरिटी एक्ट एक अप्रैल से तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश में लागू हो जाएगा। अभी 28 जिले में ही लागू हो सका है।

एक्ट लागू होने पर करीब 96 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न की जरूरत पड़ेगी। नया एक्ट आने से लीकेज खत्म हो जाएगा। निकलने वाले एक-एक ट्रक को देखा जा सकेगा। कार्डों का फर्जीवाड़ा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फर्जी कार्ड हटाकर उनको आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। इससे एक नाम पर चल रहे कई राशन कार्ड का खेल खत्म हो जाएगा। प्रयास से चीनी मिलों की देनदारियों को कम करके 3400 करोड़ पर ले आए हैं। इसमें यूपी की सिर्फ 1400 करोड़ की देनदारी ही बची है। एथेनॉल बनाने के लिए नई तकनीकी लाने जा रहे हैं।

हिन्दुस्तान 08-01-2016

भारतीय ज्यादा खाते हैं दाल, तभी बढ़े दाम : पासवान

8-1-16

कानपुर | वरिष्ठ संवाददाता

केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने दालों की बढ़ती कीमतों के लिए देशवासियों को ही कठघरे में खड़ा कर दिया। गुरुवार को कानपुर के राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में हॉस्टल का शुभारंभ करने आए पासवान ने कहा कि भारतीयों के ज्यादा दाल खाने से ही इसका संकट खड़ा हो गया है।

उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष देश में 9 लाख मीट्रिक टन दाल की मांग बढ़ रही है। विदेशों में कम पैदावार होने की वजह से ज्यादा दाल आयात की नहीं जा सकती, ऐसे में फिलहाल दाल का संकट कम होने की संभावना नहीं है।

उन्होंने कहा कि देश में 226 लाख मीट्रिक टन दाल की आवश्यकता है जबकि पैदावार 170 लाख मीट्रिक टन है। मांग और आपूर्ति में काफी अंतर आ गया है, इसलिए कीमतें बढ़ गई हैं। दाल कैश क्रॉप भी नहीं है। कमी को कम करने के लिए इसका ज्यादा आयात भी नहीं हो पा रहा है। विदेशी दाल कम खाते हैं इसीलिए बाहर पैदावार भी कम है। ज्यादा दाल आयात नहीं हो सकती है। दाल के दाम कम कराने हैं तो पैदावार बढ़ानी होगी। अन्य चीजों पर महंगाई की बात को उन्होंने सिरे से नकार दिया।

➤ अंतरराष्ट्रीय बनेगा संस्थान पेज 20

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने गुरुवार को संस्थान में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को स्मृति चिह्न भेंट किया, साथ में हैं सांसद देवेंद्र सिंह भोले।

कुछ ताकतें नहीं चाहतीं भारत-पाकिस्तान में बातचीत हो

पासवान ने पठानकोट हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। हालांकि उन्होंने भारत और पाकिस्तान में बातचीत की भी वकालत की। बोले, कुछ ताकतें नहीं चाहतीं कि भारत और पाकिस्तान में बातचीत हो। हथियारों की होड़ बंद होनी चाहिए। यूरोप में कई देशों को मिलाकर एक महासंघ बन गया है। उसी तरह एक संघ बनना चाहिए।

inext 08-01-2016

‘मोदी के एजेंडे में मंदिर नहीं विकास’

» केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान बोले, पाकिस्तान की हरकत बर्दाश्त नहीं, मिलेगा मुंहतोड़ जवाब

PIC: I NEXT

शहर प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के साथ सांसद देवेंद्र सिंह भोले.

kanpur@inext.co.in

KANPUR (7 Jan) : पठानकोट हमला भारत सरकार के बर्दाश्त के बाहर है. भारत इस हमले का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा. हमारी सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. भारत, पाक और बांग्लादेश मिलकर एक महासंघ बनाएं जोकि अच्छी पहल हो सकती है. यह सब यूरोपियन कंट्री की तरह करना चाहिए. अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आएगा तो फिर उसको छोड़ा नहीं जाएगा. यह विचार शहर प्रवास पर आए केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने गुरुवार को व्यक्त किए. राम मंदिर के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में देश का विकास है न कि राम मंदिर. इस मौके पर उन्होंने बिहार की नई गवर्नमेंट को भी कटघरे में खड़ा किया.

बिहार में माफिया हावी

रामविलास पासवान ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के 48 दिन के शासन में ही माफिया हावी हो गए हैं. नितीश कुमार का सुशासन बिहार में कभी नहीं रहा है. एक वीक में 4 इंजीनियर की हत्या कर दी गई. एमएलए राजू तिवारी से 10 लाख और मुन्नीदेवी से 1 करोड़ रुपए मोबाइल से फोन करके रंगदारी टैक्स मांगा गया है. पार्टी इस तरह के शासन को बर्दाश्त नहीं करेगी. पटना में पार्टी की संसदीय बोर्ड की मीटिंग कॉल की गई है, जिसमें आगे की रणनीति बनाकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा.

NSI को बनाएंगे वर्ल्ड क्लास » PG 5

आज 08-01-2016

दाल अब नहीं देगी दिक्कत, शक्कर मीठी

कानपुर, 7 जनवरी। कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान ने विश्वास दिलाया कि दाल की समस्या अब नहीं हो सकेगी क्योंकि सरकार पहले से ही तैयारी कर रही है। उन्होंने चीनी के दामों की बढ़ोत्तरी को तो नहीं माना गन्ना किसानों और मिल मालिकों की समस्या स्वीकारी। श्री पासवान ने कहा कि मिल मालिकों की दिक्कत दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं, राज्य सरकार चाहे तो १५ दिन में किसानों के बकाये का भुगतान करा दे। एक अप्रैल तक पूरे देश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के फायदे गिनवाते हुये श्री पासवान ने उपभोक्ता हित में जल्द ही मजबूत कानून का भी भरोसा दिलाया। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री पासवान राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में बनाये गये नये छात्रावास के उद्घाटन के लिये कानपुर आये थे। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन पर दुख जताया उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में दाल की सर्वाधिक खपत भारत में है। कई देश तो सिर्फ दाल पैदा ही इसलिये करते हैं कि वह भारत को बेच सके। पैदावार में आयी कमी और कम आयात के चलते स्थितियां बिगड़ गयीं थी लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जायेगा क्योंकि आवश्यक्ता और आपूर्ति का समन्वय बना लिया जायेगा। चीनी के दामों की बढ़ोत्तरी को नकारते हुये श्री पासवान ने कहा गन्ना किसानों का बकाया ३४०० करोड़ पर आ गया है, अकेले उ.प्र.में यह १४५० करोड़ है। राज्य सरकार अपने अधिकार का प्रयोग कर १५ दिन में यह भुगतान करवा सकती है। इसका केंद्र से लेना-देना नहीं है लेकिन मिल मालिकों की दिक्कतों को दूर करने का केंद्र प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा उपभोक्ता सुरक्षा कानून तीन दशक पुराना है और डेढ़ साल के प्रयास के उपरांत हम संशोधित बिल लाये हैं। यह स्टैंडिंग कमेटी के पास है, जिसके पास होने के बाद उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वह बिना वकील, देश के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी खरीदे गये उत्पाद की शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ गुमराह करने वाले इश्तहारों पर भी सरकार लगाम लगायेगी। इसके उपरांत श्री पासवान ने संस्थान में बने ३६ कमरों वाले छात्रावास का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके विभाग के संयुक्त सचिव प्रशांत द्विवेदी, संस्थान के निदेशक नरेंद्र मोहन तथा अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले इत्यादि मौजूद थे।

उपभोक्ता की हर शिकायत मान्य, वकील जरूरी नहीं

छात्रावास का उद्घाटन करते केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान साथ में सांसद देवेन्द्र सिंह भोले व अन्य।

15 दिन में प्रदेश दिला सकता है गन्ना का बकाया

तीन साल में शर्करा संस्थान होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का

कानपुर, 7 जनवरी। अगले तीन साल में नगर का राष्ट्रीय शर्करा संस्थान अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। यह वांयदा केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने किया। उन्होंने कहा यह आश्चर्य की बात है कि पिछले ३६ वर्षों से कोई मंत्री इस संस्थान में आया ही नहीं जबकि यह अपने आप में देश का महत्वपूर्ण संस्थान है। उन्होंने कहा वह संस्थान को लेकर गंभीर हैं क्योंकि यह आवश्यक है। श्री पासवान ने कहा अगले तीन वर्षों में इस संस्थान की ढांचागत सुविधाओं को सरकार और मजबूत करेगी, साथ ही साथ अन्य बातों पर भी ध्यान रखा जायेगा। मुझे मालुम पड़ा कि यहां पर दीक्षांत समारोह भी आयोजित नहीं किये जाते हैं, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जुलाई माह में वह फिर से कानपुर आयेंगे और संस्थान में समारोह का आयोजन किया जायेगा। जिस छात्रावास का उन्होंने उद्घाटन किया, उसमें और सुविधाओं को देने का बात भी कही।

विदेश में सिर्फ ‘मेड इन इंडिया’

कानपुर। पूरे देश में अलग-अलग नामों के उत्पाद अब विदेश में एक ही नाम तथा मार्क से बेचे जायेंगे। यह बात आज खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कही। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले उत्पाद अंतरराष्ट्री गुणवत्ता के हों ताकि अगर यह बाहरी मुल्कों में बिक्री के लिये उपलब्ध हों तो इसका पूरा लाभ मिलेगा। सरकार ने तय किया है कि यह एक ही मार्क में एक ही नाम के साथ बेचे जायेंगे। यह जरूरी है कि विदेश में उत्पाद मेड इन इंडिया के नाम से सामने हो।

दैनिक जागरण 08-01-2016

एनएसआई में आठ साल बाद होगा दीक्षांत समारोह

एनएसआई के छात्रावास की इमारत का उद्घाटन करते केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान।

कानपुर, जागरण संवाददाता : आने वाले समय में एनएसआई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकेगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इसके संकेत दिए हैं। एनएसआई में हुई प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि मंत्रालय इसमें सहायता करेगा। अन्य देशों में चीनी के उत्पादन व मांग को एनएसआई से जोड़कर देखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि 36 वर्ष से यहां कोई मंत्री नहीं आया है। आठ साल से दीक्षांत समारोह नहीं हुआ है। 20 अगस्त को दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें वह स्वयं आयेंगे। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के भुगतान में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली गई है। पहले मिल मालिकों पर किसानों का भुगतान 21 हजार करोड़ बकाया था जो अब घटकर 3400 करोड़ हो गया है। शुगर केन कंट्रोल एक्ट के अनुसार मिल मालिकों को 15 दिन के अंदर भुगतान करना चाहिए। चीनी के ऊपर आयात शुल्क 15 से बढ़ाकर 40 फीसद कर दिया गया है। इसके साथ ही एक्सपोर्ट इंसेंटिव 3300 से बढ़ाकर चार हजार रुपए कर दिया गया है। चीनी मिलों से निकलने वाले एथनाल का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया गया है। एथनाल का दाम 48.50 से 49.30 के बीच कर दिया गया है। इसके अलावा अब इसे पेट्रोल में पांच की बजाय दस फीसद मिलाने की स्वीकृति दी गई है। उद्घाटन समारोह में सांसद देवेंद्र सिंह भोले व निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन मौजूद थे।

THE PIONEER 08-01-2016

Paswan inaugurates NSI's new building

PIONEER NEWS SERVICE ■ KANPUR

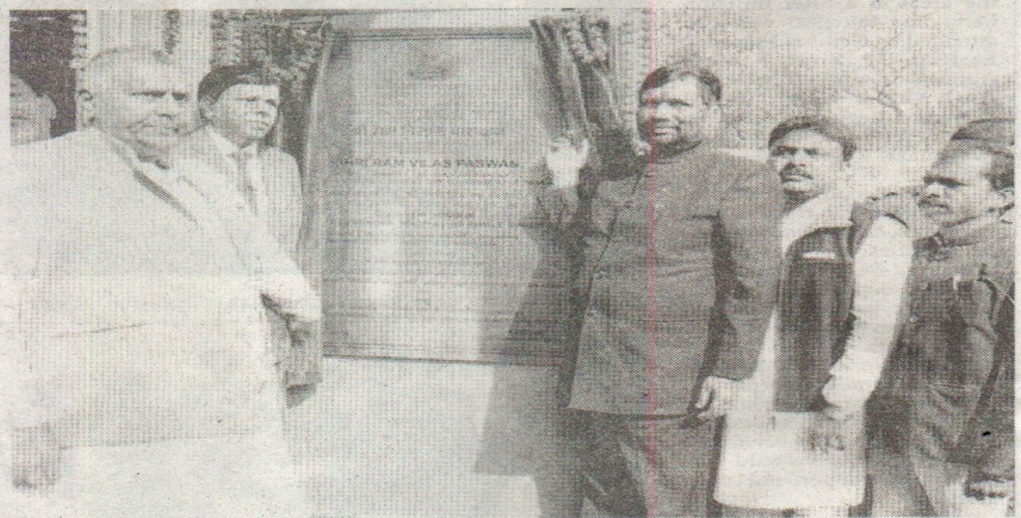

Union Food Minister, Ram Vilas Paswan inaugurating the newly-constructed building at NSI on Thursday. Pioneer

The Union Food Minister, Ram Vilas Paswan while inaugurating the new building of the National Sugar Institute on Thursday underlined the need for paradigm shift in formulating and implementing the agricultural research programme. The diverse challenges and constraints on account of the population boom there was need to ensure of better quality of sugarcane so at to stand at par with the sugar producing nations of the world. The emerging scenario necessitated the institutions to have perspective vision which could be translated through proactive, novel and innovative research approach based on cutting edge science.

He praised the efforts of the NSI which had been doing a yeoman's service in the field of better sugar production and focusing on feasibility and economy as well. He said there has been tremendous development in this institute in the past two years. The Ministry was committed to ensure further development of this prestigious institute.

He said there was also a need for the upgradation of the currculam and arm the institute with better and modern equipment which can help not only increase the yield but ensure that the sugar quality was world class.

Addressing the gathering the Director of the NSI, Prof Narendra Mohan said sugarcane supported one of the largest agro-processing industries of the country and millions of farmers were engaged in its cultivation. He said in addition to this around half a million skilled and semi-skilled workers, mostly from rural areas were also engaged in the sugar industry. He said by 2030 India will require nearly 33 million tonnes of white sugar for domestic consumption alone. He said production of alcohol for partial replacement of fossil fuel and use of bagasse in cogeneration of electricity had great potential in future and thus requirement of cane will increase further.

Dr Prashant Trivedi, Joint Secretary Sugar Administration said an average sugar recovery of 10.75 per cent, about 520 million tonnes of sugarcane will have to be produced and this will entail an increase in sugarcane productivity to the tune of 100 to 110 tonnes/ha, as area may stabilise around 5 million hectare.

He said the Indian Institute of Sugarcane Research (IISR), Lucknow had developed several technologies to enhance sugarcane productivity in the country and has to gear itself to address new challenges to ensure sustainable sugarcane production in future as well.

दैनिक जागरण 08-01-2016

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में होगा बड़ा बदलाव

8-1-16

कानपुर, जागरण संवाददाता : उपभोक्ताओं को अपने अधिकार के लिए कानूनी दांव पेंच में नहीं उलझना होगा। उपभोक्ता अदालत की प्रक्रिया आसान करने की तैयारी चल रही है। सरकार ने 29 वर्ष से चले आ रहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बड़ा बदलाव किया है। इससे उपभोक्ता को देश के किसी भी कोने में बैठकर अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार मिलेगा। फिर चाहें उसने सामान किसी दूसरे शहर से खरीदा हो। ये बातें राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) में खाद्य एवं जन वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहीं।

परिसर में नए छात्रावास का उद्घाटन करने आए श्री पासवान ने बताया कि न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने, वकील का झंझट व राष्ट्रीय स्तर पर अपील खत्म करने समेत कई बिंदु नए एक्ट में शामिल किए गए हैं। एक्ट में बदलाव लोकसभा में पास हो चुका है। एक्ट के अनुसार 21 दिन में उपभोक्ता की शिकायत खुद दर्ज मानी जाएगी। जिला व प्रदेश स्तर पर वादी की जीत के बाद विपक्ष खास परिस्थितियों में ही राष्ट्रीय स्तर पर अपील कर सकेगा। सामान्य परिस्थितियों में वादी को जीता माना जाएगा। एक्ट में दोनों पक्षों में समझौता प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा

शेष पृष्ठ 20 पर (देखें पेज-4)

कानूनी दांव-पेंच नहीं

- कहीं से भी शिकायत दर्ज कर सकेंगे उपभोक्ता, न्यायिक प्रक्रिया होगी आसान
- 21 दिन में खुद दर्ज होगी, खाद्य एवं जन वितरण मंत्री रामविलास पासवान बोले

THE TIMES OF INDIA 08-01-2016

FSA to be enforced from April 1

TIMES NEWS NETWORK

Kanpur: Union minister Ram Vilas Paswan said that from April 1, Food Security Act will come into force. He was at the National Sugar Institute (NSI) to inaugurate a student hostel.

He emphasized that 'Make In India' products would be of international quality. He said that in three years, NSI would be developed as an institute of international standard. Dues of sugarcane farmers amounting to Rs 12,000 crores have come down to Rs 3,400 crores. Of this, Rs 1,450 crores are the dues of sugarcane farmers of Uttar Pradesh.

"After implementation of Food Security Act, every individual will get five kgs of grain in a month. He will get wheat at Rs 2 per kg and rice at Rs 3 per kg. APL and BPL card system will end," Paswan added.

He mentioned that the country would be requiring 610 lakh metric tonnes of food grains after implementation of FSA Act. "UP alone will require 96 lakh metric tonnes," he added. The implementation of the FSA Act will ensure that all the depots are online and it could be known easily how much stock is kept in the godowns.

राष्ट्रीय सहारा 08-01-2016

'एनएसआई बनेगा अंतरराष्ट्रीय संस्थान'

कानपुर (एसएनबी)। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने गुरुवार को नगर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) को अंतरराष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाने का दम भरा। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिश की जायेगी कि शर्करा रिसर्च व अध्ययन क्षेत्र में संस्थान की ख्याति दुनिया भर में फैले।

पत्रकारों से वार्ता करते केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान।

केन्द्रीय मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख यहां एनएसआई में बने नये छात्रावास का उद्घाटन करने आये थे। करीब ढाई करोड़ की लागत से निर्मित 36 कमरों वाले इस छात्रावास में बेहतर बिजली फिटिंग, लाइब्रेरी, मनोरंजन कक्ष, पैंट्री व डायनिंग हॉल आदि की व्यवस्था है। केन्द्रीय मंत्री ने गत दो वर्षों में संस्थान द्वारा किये गये कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस संस्थान को अंतरराष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाने हेतु आवश्यक सुविधायें मुहैया करा दी जायेंगी। संस्थान को कक्षाओं व प्रयोगशालाओं के उच्चीकरण, नये प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व आवश्यक नवीनतम अनुसंधान उपकरणों के लिए मदद दी जायेगी। उन्होंने चीनी मिलों द्वारा बिजली उत्पादन करने की दिशा में संस्थान द्वारा किये जा रहे कार्यों को और तेज करने की अपेक्षा की। साथ ही उन्होंने उप्र में गन्ने का उत्पादन और बढ़ाने पर भी जोर दिया, जिससे किसानों को सीधे लाभ हो सके।

■ केन्द्रीय मंत्री ने किया 36 कमरों वाले नये छात्रावास का उद्घाटन

इस अवसर पर पधारे सांसद अकबरपुर देवेन्द्र सिंह 'भोले' ने अपेक्षा जतायी कि संस्थान चीनी क्षेत्र में विकास की नयी राह सुझायेगा। भारत सरकार से संबद्ध संयुक्त सचिव (शर्करा-प्रशासन) ने आशा जतायी कि संस्थान व मंत्रालय के सामूहिक प्रयास से निर्धारित कार्य लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र कर ली जायेगी। संस्थान के निदेशक नरेन्द्र मोहन ने मंत्री सहित अन्य अतिथियों को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्थान को विश्वविख्यात संस्थान के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य योजना शीघ्र मंत्रालय को प्रेषित कर दी जायेगी। उन्होंने संस्थान को दिये जा रहे प्रोत्साहन के लिए भी मंत्रालय का आभार जताया।

■ **संस्थान का किया निरीक्षण, छात्रों से भी मिले**

केन्द्रीय मंत्री ने संस्थान की कक्षाओं व प्रयोगशालाओं का निरीक्षण करने के साथ ही छात्रों से भी बातचीत की। उन्होंने यहां से निकले छात्रों के शत-प्रतिशत प्लेसमेंट पर हर्ष जताया। छात्रों से बातचीत के दौरान केन्द्रीय मंत्री ने सभी को उद्यमशीलता के लिए प्रेरित किया।

पाक को करारा...

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) में 2.50 करोड़ की लागत से निर्मित नये छात्रावास के शुभारंभ में आये थे। मीडिया से उन्होंने राम मंदिर पर कहाकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एजेंडा डेवलपमेंट है। प्रधानमंत्री के अलावा राम मंदिर पर कोई कुछ कहता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। पूरे देश में समान कर प्रणाली के लिए प्रस्तावित जीएसटी बिल पर कहाकि कांग्रेस व बसपा नहीं चाहती है कि यह बिल पास हो। दोनों पार्टियां इसे लटकाये रखना चाहती हैं। उन्होंने पठानकोट में आतंकी हमले को लेकर पाक को करारा जवाब देने की बात कही।

THE TIMES OF INDIA 08-01-2016

Paswan flays 'lawless' Nitish govt

TIMES NEWS NETWORK

Kanpur: Union minister Ram Vilas Paswan on Thursday launched an attack on Nitish Kumar and Lalu Yadav alliance government in Bihar, saying his party MLAs Raju Tiwari and Munni Devi have been asked to pay 'rangdari' (protection money) of Rs 10 lakhs and Rs 1 crore respectively. Paswan said that Raju has also been threatened that he would be killed if he does not pay the money.

"This shows lawlessness prevailing in Patna. There does not exist any government in Bihar," Paswan told reporters.

Paswan said that 'jungle raj' has returned in Bihar and cases of kidnapping, rape, murder and extortion are on the rise. He condemned the killing of four engineers in Bihar. The minister added that his son Chirag Paswan would launch state-wide protest against Nitish-Lalu government on January 10.

Talking to reporters at the National Sugar Institute here, he said: "We had decided to watch the Bihar government's functioning for six months before any agitation but 'jungle raj' has returned in just two months, forcing us to take to roads soon."

▶Continued on P 2

inext 08-01-2016

एनएसआई को बनाएंगे वर्ल्ड क्लास

» कैबिनेट मिनिस्टर राम विलास पासवान ने संस्थान के 36 सीटर के नए हॉस्टल का लोकार्पण किया

» बोले, फूड सिक्योरिटी के आने से लीकेज खत्म हो जाएगा, अब सारा डाटा ऑनलाइन मिल जाएगा, इसे आधार कार्ड से भी कनेक्ट किया जाएगा

8-1-16

इस साल भी नहीं गलेगी दाल

दाल की महंगाई पर बोलते हुए सेंट्रल मिनिस्टर ने कहा कि लास्ट इयर भी दाल की फसल का उत्पादन कम हुआ था. करीब करीब हालत इस बार भी वही है. इस बार भी दाल की फसल अच्छी नहीं होगी. देश में दाल की कुल खपत करीब 235 लाख मीट्रिक टन है. दाल की उपज करीब 172 लाख मीट्रिक टन होगी. इंडिया में जितनी दाल का उत्पादन किया जाता है वह सब खाली जाती है. इंडियन दाल बहुत खाते हैं. विदेशों में जो दाल का उत्पादन होता वह इंडिया की मार्केट में बेची जा रही है. सरकार की लगातर इस पर नजर बनी हुई है. देश में अतिरिक्त चीनी का उत्पादन हुआ है अब 30 लाख मीट्रिक टन चीनी विदेश में निर्यात की जाएगी.

PIC: I NEXT

हॉस्टल का लोकार्पण करते हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान व सांसद देवेंद्र सिंह.

kanpur@inext.co.in

KANPUR (7 Jan): एनएसआई पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि ढाई साल पहले फूड सिक्योरिटी एक्ट बन गया था लेकिन यूपी के मात्र 28 जिलों में ही लागू हो पाया है. जिन जिलों में एक्ट नहीं लागू हो पाया वहां पर एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय योजना का लाभ दिया जा रहा है. फूड सिक्योरिटी के आने से लीकेज खत्म हो जाएगा. सारा का सारा डाटा ऑनलाइन मिल जाएगा. कार्ड को आधार कार्ड से कनेक्ट करने की दिशा में भी काम हो रहा है. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एनएसआई में 36 सीटर हॉस्टल का लोकार्पण करते हुए कहीं.

कंज्यूमर एक्ट में बदलाव

खाद्य मंत्री पासवान ने इस मौके पर कहा कि पेट्रोल में दस परसेंट एथेनॉल मिलाया जा रहा है. जिसका उत्पादन 30 चीनी मिलें कर रही हैं. पिछले साल तक पेट्रोल में 5 परसेंट एथेनॉल मिलाया जा रहा था. उन्होंने कंज्यूमर एक्ट में किए बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि कंज्यूमर ने अगर जिला व स्टेट कंज्यूमर फोरम में वाद जीत लिया तो फिर नेशनल फोरम में सुनवाई नहीं होगी. साथ ही अगी कंज्यूमर अपनी शिकायत रजिस्टर्ड डाक से भेजता है तो 21 दिन में कम्प्लेन को ही खुद-ब-खुद वाद दर्ज मान लिया जाएगा. एनएसआई के डायरेक्टर प्रो नरेन्द्र मोहन ने चीफ गेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर रामविलास पासवान का वेलकम किया. इस मौके पर पासवान ने कहा कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर इसे वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा. सांसद देवेंद्र सिंह भोले, प्रशांत त्रिवेदी आदि मौजूद रहे.

पेट्रोल में दस परसेंट एथेनॉल मिलाया जा रहा है. जिसका उत्पादन 30 चीनी मिलें कर रही हैं.

जीएसटी का विरोध करने वाले कांग्रेसी राष्ट्रद्रोही

संसद में जीएसटी बिल का विरोध करने वाली कांग्रेस राष्ट्रद्रोही है. राम मंदिर के मुद्दे पर जब सवाल किया गया तो मिनिस्टर ने साफ किया कि किसी की निजी राय हो सकती है इस मामले पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रुख बिल्कुल साफ है. उनका एजेंडा सिर्फ देश का विकास है. पीएम ने किसी भी विवादित मामले पर कभी कोई बयान नहीं दिया है.

अमर उजाला 08-01-2016

कहीं भी खरीदें सामान, कहीं भी करें शिकायत

नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में आए केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने दी जानकारी, कहा खुद पैरवी कर सकेंगे उपभोक्ता

अमर उजाला ब्यूरो

कानपुर। आम उपभोक्ता को राहत देने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1985 में बदलाव किया है। इसका मसौदा लोकसभा से पास हो गया। अब स्टैंडिंग कमेटी मामले का अध्ययन कर रही है। जल्द ही उपभोक्ताओं को लड़ने और कार्रवाई का नया अधिकार मिल जाएगा। जैसे कहीं भी शिकायत दर्ज कराने की छूट होगी। उपभोक्ता खुद अपने मामले की पैरवी कर सकेगा। इसी सिलसिले में 16 जनवरी को कर्नाटक में मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें केंद्र, राज्य और जिला उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन, सदस्य शामिल होंगे। उपभोक्ता फोरम को मजबूत बनाने पर मुहर लगेगी। साथ ही हर जिले में उपभोक्ता फोरम बनाने और चेयरमैन के खाली पदों को भरने की हरी झंडी मिलेगी। शहर आए केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने यह जानकारी देते हुए कहा कि फोरम की न्यायिक प्रक्रिया सरल और प्रभावी बनाई गई है।

यह होगी प्रक्रिया

भ्रामक विज्ञापनों का मामला भी उपभोक्ता फोरम देखेगी। 21 दिन के अंदर ही शिकायतों का उपभोक्ता फोरम में आटोमेटिक रजिस्ट्रेशन। जिला और राज्य उपभोक्ता फोरम के सही मामलों की अपील केंद्रीय उपभोक्ता फोरम में नहीं की जा सकेगी। उपभोक्ता फोरम की जद में सरकारी सिस्टम भी। जितनी समयसीमा में मकान, प्लाट या फिर फ्लैट देने का पैसा लिया जाएगा, उसे पूरा करना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो फोरम प्रभावी कार्रवाई करेगा।

एनएसआई में एससी गुप्ता छात्रावास का उद्घाटन करते केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान, सांसद देवेन्द्र सिंह भोले और निदेशक प्रो. नरेन्द्र मोहन।

अब हर प्रोडक्ट पर होगा बीआईएस का टैग

मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) 1986 का बिल भी बदला गया है। अब कोई भी कंपनी जो प्रोडक्शन का मानक पूरा करती है, वह इंडियन स्टैंडर्ड का लोगो खुद लगा सकेगी। किसी इंस्पेक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रोडक्ट पर डेट ऑफ मैन्यूफैक्चरिंग और एक्सपायरी का लिखा जाना जरूरी है। इस व्यवस्था से भारतीय प्रोडक्ट की अंतरराष्ट्रीय साख सुधरेगी। मार्केट में इंडियन स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट की धूम होगी।

देश में पौने तीन करोड़ फर्जी राशन कार्ड पकड़े

कानपुर। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ी धांधली का खुलासा करते हुए बताया कि डेढ़ साल के अंदर देश में तीन करोड़ 75 लाख राशन कार्ड फर्जी पाए गए हैं। इन सबको राशन और मिट्टी का तेल नहीं दिया जा रहा है। अभी और भी मामले सामने आएंगे। इस मामले की जांच कराई जाएगी। पासवान ने बताया कि 1 अप्रैल से देश के ज्यादातर राज्यों (कर्नाटक को छोड़कर, जहां चावल, गेहूं फ्री उपलब्ध है) में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो जाएगा, सभी जरूरतमंदों को राशन मिलने लगेगा। यूपी के 27 जिलों में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो गया है। राज्य सरकार ने मार्च के अंत तक सभी जिलों को इसके दायरे में लाने का भरोसा दिलाया है। एक्ट लागू होने के बाद यूपी में 96 लाख टन राशन की जरूरत पड़ेगी। इस मौके पर भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रशांत त्रिवेदी, एनएसआई के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन, एफसीआई लखनऊ के जीएम देवेंद्र सिंह चौहान, कमलावती सिंह मौजूद रहीं।

पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत

पठानकोट एयरबेस हमले पर पासवान ने अपनी सरकार को घेरा, जीएसटी लटकाने पर कांग्रेस को कहा राष्ट्रविरोधी

कानपुर। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने गुरुवार को पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले और सात जवानों के शहीद होने का मामला उठाते हुए अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। सेना को पूरा अधिकार भी है, वह टिट फॉर टैट (जैसे को तैसा) के अंदाज में जवाब दे सकती है। केंद्रीय मंत्री ने भाजपा महासचिव राम माधव के अखंड भारत के उलट बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत को महासंघ बनाने की जरूरत है, जैसा कि यूरोपीय संघ है। राज्यसभा में जीएसटी बिल को लटकाने वाली कांग्रेस को राम विलास पासवान ने राष्ट्रविरोधी करार दिया। कहा कि कांग्रेस को जनता ने सबक सिखाया है। सुधारों में अड़ंगा लगाने से कोई फायदा नहीं होगा।

केंद्रीय मंत्री गुरुवार को यहां नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (एनएसआई) पहुंचे और 72 सीट वाले नए हॉस्टल का उद्घाटन किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में विधायकों से रंगदारी मांगी जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक राजू तिवारी से 10 लाख रुपये और मुन्नी देवी से एक करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। जान से मारने की धमकी भी मिली है। इस मामले को पार्टी जोरदार तरीके से उठाएगी। 10 जनवरी को पटना में आंदोलन किया जाएगा। पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नीम और लालू प्रसाद यादव को करेला कहा। साथ ही जोड़ा कि बिहार में जंगलराज की वापसी हो गई है। पासवान ने राम मंदिर के निर्माण से संबंधित सवाल पर सधी प्रतिक्रिया दी। साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगल एजेंडा देश का विकास है। प्रधानमंत्री राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दों पर नहीं बोल रहे हैं। कोई कुछ बोले फर्क नहीं पड़ता है।

थपथपाई पीठ

महंगाई के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार की पीठ थपथपाई और कहा कि चावल, गेहूं, टमाटर, प्याज सहित तमाम खाद्य पदार्थों के दाम कम हुए हैं। दाल का मामला प्रोडक्शन पर फंसा है। भारतीय जितनी दाल पैदा करते हैं, उतनी खा जाते हैं। विदेशों में दाल की जो खेती है, वह खाने के लिए नहीं, बल्कि भारत भेजने के लिए की जाती है। 2016 में 235 लाख टन दलहन की जरूरत है लेकिन पैदावार 180 लाख टन होने का अनुमान है। इस अंतर को कम करने की कवायद जारी है। शत्रुघ्न सिन्हा के मामले में कहा भाजपा में बोलने की आजादी है, जिसका फायदा बिहारी बाबू उठा रहे हैं।

'अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा एनएसआई'

कानपुर। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (एनएसआई) का दीक्षांत समारोह 20 अगस्त को होगा। इसमें उपभोक्ता मामले के केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान भी शामिल होंगे। इसकी पुष्टि खुद मंत्री ने की है। एनएसआई का दीक्षांत समारोह लंबे समय से नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के एक मात्र इंस्टीट्यूट को अगले तीन साल के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यूजी, पीजी कोर्स की सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने गुरुवार को एनएसआई में 32 कमरे और 72 सीटों वाले नए हॉस्टल का उद्घाटन किया। लैब, लाइब्रेरी और क्लास रूम देखा। प्रैक्टिकल के लिए बनाई गई चीनी मिल में भी गए। इसके बाद मीडिया से कहा कि 1980 के बाद एनएसआई में केंद्रीय मंत्री का आगमन हुआ है। एनएसआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा। चीनी उत्पादन में ब्राजील नंबर-वन है लेकिन वहां कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। एनएसआई की मदद से गन्ना पैदावार, चीनी उत्पादन, एथेनॉल और अल्कोहल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने कहा कि इस बार इंटरनेशनल कांफ्रेंस में एनएसआई के दो शोध पत्र पढ़े जाते हैं।

विदेशियों का स्वाद बढ़ाएगी भारतीय चीनी

कानपुर। भारतीय चीनी अब विदेश भेजी जाएगी। श्रीलंका, अफ्रीकी देश, बांग्लादेश और मध्य एशिया के कई देशों को चीनी भेजने का समझौता हुआ। पहली बार 30 लाख टन चीनी भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश की 530 चीनी मिलों के पास 90 लाख टन चीनी का भंडार है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (एनएसआई) के प्रोग्राम में हिस्सा लेने आए उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रशांत त्रिवेदी ने बताया कि देश में 260 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है, जबकि मांग 240 लाख टन की है। 20 लाख टन ज्यादा पैदा होने वाली चीनी को दूसरे देशों को भेजने का फैसला पहली बार लिया गया। उन्होंने बताया कि नवंबर 2015 से दिसंबर 2016 के बीच 120 करोड़ लीटर एथेनाल पेट्रोल में मिलाकर बेचा जाएगा। इसके लिए 130 चीनी मिलें ऑयल कंपनियों को एथेनाल बेच रही हैं। प्रति किलोग्राम एथेनाल 48 से 49 रुपये में खरीदा जा रहा है, जिसका सीधा फायदा किसान और चीनी मिलों को मिल रहा है। ब्राजील के बाद भारत सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। एथेनाल पर एक्साइज ड्यूटी की छूट और बढ़िया रेट से चीनी मिलों का नजरिया बदलेगा। वह गन्ना लेंगे और शीरे से एथेनाल पर जोर देंगे। इससे चीनी के उत्पादन में कमी आएगी। अभी 20 लाख टन ज्यादा चीनी उत्पादित की जा रही है।